(c) In view of reply to part (b) above, question does not arise.

Irregularities in NRI Accounts

2752. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the nature of the irregularities in the operation of the foreign currency (Non-resident) Accounts operated by banks that have come to light impelling the Reserve Bank of India to order a special audit;

(b) the period over which such irregularities have been committed and the total loss of foreign exchange to the country as a result; and

(c) the number and names of foreign banks involved in the irregularities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) A special audit has been instituted by the Reserve Bank of India to reconcile the books of the Reserve Bank of India and the authorised dealers handling foreign currency non-resident accounts transactions in order to locate any discrepancies in interest claims and purchases made by the authorised dealers from the Reserve Bank of India with reference to the exchange rate at which the principal deposit was sold to the Reserve Bank of India. The auditors have been advised to cover a period of four years from April 1, 1990 to March 31, 1994. The special audit is not complete and a definitive view on irregularities cannot be taken at this stage.

Foreign Exchange Reserves

2753. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is proposed to introduce further liberalisation of imports in view of rising foreign exchange reserves; and

(b) if so, the details of new liberalisation methods proposed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Foreign currency assets of the Reserve Bank of India have risen from $ 15.1 billion at the end of March 1994 to $ 17.5 billion at the end of July 1994. A number of measures are being taken to moderate the inflationary impact of rising foreign exchange reserves. The Government is constently monitoring the situation and suitable measures will be taken as and when required.

लघु उद्योगों को ऋण

2754. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को ऋण मंजूर करने के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों और संस्थाओं को लघु उद्योगों/उद्यमियों से ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितना ऋण मंजूर किया गया;

(घ) क्या ऋण मंजूर करने में विलम्ब के कारण अनेकों उद्योग रुग्ण हो गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई ऋण नीति के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में 60 लाख रुपए तक (अनुषंगी इकाइयों और निर्यातोन्मुख इकाइयों के मामले में 75 लाख रुपए) के निवेश वाले लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे ग्रामोद्योगों, अति लघु उद्योगों और लघु उद्योग क्षेत्र की दूसरी इकाइयों को उस क्रम में वरीयता दें। बैंकिंग प्रणाली से कुल एक करोड़ रुपए तक की निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले ग्रामोद्योगों, अति लघु उद्योगों और लघु उद्योग क्षेत्र की दूसरी